भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1198

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

निर्मल ग्राम

1198. श्री हुसैन दलवई:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक राज्य–वार कितनी ग्राम–पंचायतों ने निर्मल ग्राम का दर्जा प्राप्त किया है;

(ख) शेष ग्राम पंचायतों को दायरे में लाने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किए जाने का विचार है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) : 12 दिसम्बर, 2013 तक 28002 ग्राम पंचायतों ने निर्मल ग्राम दर्जा प्राप्त कर लिया है, राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2017 तक 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतें निर्मल ग्राम का दर्जा प्राप्त कर लें।

(ग) : 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण स्वच्छता के लिए 37,159 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यनीतियों के साथ समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) में व्यापक बदलाव किया है, जिसे अब निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के नाम से जाना जाता है :

(i) समग्र स्वच्छता परिणामों के लिए ग्राम पंचायत भागीदारी प्रक्रिया में सभी समुदायों को शामिल करते हुए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देना।

(ii) 2012-2017 के लिए एक राष्ट्रीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एडवोकेसी और संचार कार्यनीति ढांचे को स्वीकारना और उसका कार्यान्वयन करना।

(iii) ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ संयुक्त रूप से कार्य करना।

(iv) स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित संबद्ध मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए) के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करना।

(v) एमजीएनआरईजीएस के तालमेल में परियोजना प्रक्रिया पद्धति के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के घटक का पुनर्गठन करना।

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमएनआरईजीएस) के साथ तालमेल कर व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु 4500 रुपए की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान।

(vii) आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने संबंधी प्रावधान को गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले अभिज्ञात एपीएल परिवारों (समस्त अनु.जातियों/अनु.जनजातियों, लघु एवं सीमांत किसानों, वासभूमि के साथ भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिला प्रधान परिवार) के लिए भी उपलब्ध किया गया है।

*****

अनुबंध -I

राज्य सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1198 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनजीपी पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतें
1.	आंध्र प्रदेश	1273
2.	अरुणाचल प्रदेश	31
3.	असम	31
4.	बिहार	217
5.	छत्तीसगढ़	817
6.	गुजरात	2281
7.	हरियाणा	1578
8.	हिमाचल प्रदेश	1011
9.	जम्मू एवं कश्मीर	14
10.	झारखंड	225
11.	कर्नाटक	1069
12.	केरल	980
13.	मध्य प्रदेश	2068
14.	महाराष्ट्र	9523
15.	मणिपुर	2
16.	मेघालय	588
17.	मिजोरम	89
18.	नागालैंड	90
19.	ओडिशा	284
20.	पंजाब	166
21.	राजस्थान	321
22.	सिक्किम	164
23.	तमिलनाडु	2385
24.	त्रिपुरा	113
25.	उत्तर प्रदेश	1080
26.	उत्तराखंड	525
27.	पश्चिम बंगाल	1077
	कुल	**28002**